

बारिश की हर बूंद सहेजने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी, 'कैच द रेन' अभियान में नंबर-1

नई दिल्ली,02 सितंबर 2026। बारिश के पानी को सहेजने और भूजल पुनर्भरण के प्रयासों में छत्तीसगढ़ ने देश में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। जलशक्ति मंत्रालय के 'जल संचयन जन भागीदारी' और 'कैच द रेन' अभियान में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए तीसरे चरण में देश में पहला स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली के सुप्रीम स्वराज भवन में आयोजित जलशक्ति मंत्रालय के विभागीय शिक्षण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। सम्मेलन के 'कैच द रेन' सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने देशभर में जल संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए हर राज्य का अपना 'कैच द रेन' प्लान, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए 'स्टेट वाटर अवार्ड्स', बिसाग-एन के माध्यम से जल संरचनाओं की मैपिंग और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर तीन महीने समीक्षा का सुझाव दिया। साय ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं और अपने गांव बगिया में स्वयं हल चलाकर खेती कर चुके हैं इसलिए पानी की कीमत को करीब से समझते हैं। उन्होंने बताया कि देश के कुल क्षेत्रफल में करीब 4 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला छत्तीसगढ़ 'जल संचयन जन भागीदारी' अभियान में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। राज्य ने जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर किसानों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जनअभियान का रूप दिया है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से शुरू हुए '5 प्रतिशत मॉडल' को जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण की अगुआई पहल बताया। इसके तहत किसान स्वेच्छ से अपनी जमीन का 5 प्रतिशत हिस्सा भू-जल पुनर्भरण के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इस भूमि पर बारिश के पानी को रोकने और उसे धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंचाने के लिए जल संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। खेतों में बनाई गई इन संरचनाओं में बारिश का पानी एकत्र होता है और धीरे-धीरे जमीन में समाहित होता है। इससे भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने तथा सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।



राम मंदिर के पहले सीईओ बने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा

चंपत राय की जगह गोविंद देव गिरि महासचिव बने ट्रस्ट में 3 नए सदस्य शामिल

अयोध्या,02 सितंबर 2026। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को लेकर निर्णय हो गया है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के सीईओ चुने गए हैं। बुधवार को अयोध्या की मणि रामदास छावनी में महंत नृत्यगोपालदास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बैठक में ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ ही आमंत्रित सदस्य भी मौजूद रहे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि को नया महासचिव बनाया गया है। बैठक में ट्रस्टी बनाए गए महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष का चार्ज दिया गया। वहीं,ट्रस्ट की बैठक में तीन नए सदस्यों की भी घोषणा की गई है। नए शामिल होने वाले सदस्यों में मदन मोहन पांडेय अयोध्या के,महेश भागचंदका दिल्ली के और निर्मला यादव अयोध्या से हैं। ट्रस्ट ने एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को मंदिर का पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके मिश्रा अब राम मंदिर की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को नई दिशा देंगे। एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा मूल रूप से देवरिया जिले के

भाटापारानी क्षेत्र के भोपतपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था। अपने लंबे सैन्य करियर में उन्होंने 18 से अधिक प्रकार के विमानों पर उड़ान भरी और 3,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव हासिल किया। कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर भी रहे हैं। इसके अलावा एकीकृत रक्षा स्टाफ में उप प्रमुख (सिद्धांत,संगठन एवं प्रशिक्षण) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। देश के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मिश्रा के पास बड़े संगठन के संचालन और नेतृत्व का व्यापक अनुभव है। राम मंदिर के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मंदिर अब निर्माण के चरण से आगे बढ़कर व्यवस्थित संचालन और वैश्विक धार्मिक-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था,कर्मचारी प्रबंधन, सुविधाओं का विस्तार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियां सीईओ के सामने होंगी।



ट्रस्टी मदन मोहन पांडेय बोले...चंपत राय के खिलाफ कोई कोई आरोप नहीं

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सदस्य मदन मोहन पांडेय ने कहा...सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उसने पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराई। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जीता और मंदिर का निर्माण हुआ। इससे पहले वहां क्या था? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा- यात्रियों के लिए सुविधाएं और मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक कोई समस्या नहीं है, फिर और क्या चाहिए? पर्याप्त सुविधाएं हैं और आगे भी उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। चंपत राय या किसी अन्य के खिलाफ कोई आरोप नहीं है।

वीएचपी अध्यक्ष बोले...जीतेंद्र मिश्रा के अनुभव से ट्रस्ट को फायदा होगा

वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासियों ने कई अच्छी खबरें दी हैं। यह पूरे हिंदू समाज के लिए खुशी का विषय है। गोविंददेव गिरि महाराज अब ट्रस्ट के महासचिव हैं। प्रशासनिक अनुभव की जरूरत को देखते हुए सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है।

जीडीपी के आंकड़ों में खेल कर रही सरकार,पूर्व वित्त सचिव ने बताया कि असल ग्राथ 2.6 फीसदी : जयराम

नई दिल्ली,02 सितंबर 2026। कांग्रेस ने सरकार के 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के आकलन के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि करीब 2.6 प्रतिशत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए अर्थव्यवस्था की तस्वीर चमकाने की कोशिश कर रही है, जबकि यह जमीनी हकीकत से अलग है। कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार अपनी टीम और मीडिया के जरिए जितना फर्जी जीडीपी बढ़ोतरी का खेल पीटोगी, उतना ही उसकी असलियत सामने आएगी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं और उनका आकलन है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत के बजाय करीब 2.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत हो, लेकिन मजबूत अर्थव्यवस्था का रास्ता आंकड़ों को सजाने से नहीं,बल्कि वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने से निकलता है। सरकार को पहले अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए और उसके बाद सुधारों की दिशा में कदम उठाने चाहिए। जयराम ने कहा कि सरकार को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा मांग और आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।



वित्त मंत्री सीतारमण ने की विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा से मुलाकात,सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

नई दिल्ली,02 सितंबर 2026। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात कर भारत तथा इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक्स पोस्ट में बताया कि सीतारमण ने मंगलवार को एशविले में जी20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएएमसीबी जी) की बैठक से इतर विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा मुलाकात की। वित्त मंत्री ने भारत के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लगातार जुड़ाव की सराहना की और 1.5 अरब डॉलर की डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग (डीपीएफ) की तेजी से प्रोसेसिंग को सराहा। इस मुलाकात



के दौरान सीतारमण ने सिडबी के जरिए एमएसएमई को आईएफसी से मिले सहयोग की भी तारीफ की। इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और इसका एमएसएमई सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ा है। दोनों नेताओं ने भारत-वर्ल्ड बैंक समूह की साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें भारत में एमआईजीए की बड़ी

भूमिका पर विचार करना भी शामिल था,ताकि गाट्टी के व्यवस्थित इस्तेमाल और प्राइवेट कैपिटल को ज्यादा जुटाकर कॉर्पोरेट,इंफ्रास्ट्रक्चर और म्युनि सिपल बॉन्ड मार्केट को गहरा किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट बढ़ाने के वास्ते सेक्टर-आधारित,प्रोग्राम-आधारित

अप्रोच पर भी चर्चा हुई। बंगा ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में आए बड़े बदलाव की सराहना की और भारत के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साधनों का और फायदा उठाने के मौकों पर ध्यान दिया। इसमें एमआईजीए की भागीदारी और विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए पॉलिटिकल रिस्क इश्योर्स शामिल है। वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत में 'ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज हब' बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ भारत के जुड़ाव पर भी जोर दिया। इसमें खेती जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के मौकों पर विचार करना शामिल है।

एनपी के रीवा में बड़ा हदसा...सीपी मार्ग पर बस-बल्कर में मिट्टी,3 मौत 10 से ज्यादा लोग घायल

रीवा,02 सितंबर 2026। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। यह हादसा बदवार स्टैंड के पास हुआ है। सीधी की ओर से आ रही पवन एक्सप्रेस बस और रीवा की ओर से आ रहे बल्कर के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें तीन लोगों के मौत हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत गुड़ थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। दुर्घटना में लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से संजय गांधी अस्पताल रीवा भर्ती कराया गया। रीवा हजूर एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि बस में 43 लोग सवार थे।

अमेरिका ने ईरान में शादी समारोह पर हमला किया:19 की मौत,68 घायल,ईरान का जॉर्डन-बहरीन में जवाबी अटैक

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान,02 सितंबर 2026। अमेरिका ने ईरान पर दूसरी बार हमला किया है। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात सिरिक, खुजस्तान, केशम द्वीप और बंदर अब्बास पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरान के मुताबिक सिरिक में एक शादी समारोह के दौरान मिसाइल गिराए गए। इसमें 19 लोगों की मौत हुई जबकि 68 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हमले के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में घायल बच्चे अस्पताल में इलाज कराते दिख रहे हैं। वहीं, खुजस्तान प्रांत पर हमले में 7 लोगों की मौत हो गई,जबकि 8 लोग घायल हुए। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों



को निशाना बनाने का दावा किया है। इसमें कई लोगों मारे गए हैं। अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन बुधवार को थाईलैंड पहुंचा। यह युद्धपोत 200 दिनों से ज्यादा समय तक लगातार समुद्र में रहने के बाद पांच दिन के आराम के लिए यहां रुका है। इस पोत पर करीब 5,000 सैनिक और कर्मचारी तैनात हैं। यह पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े मिशन पर था। लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण जहाज पर तैनात लोगों को किसी

बंदरागार पर रुकने का मौका नहीं मिला। इसी वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य और रहने की परिस्थितियों को लेकर भी चिंता जताई गई है। ईरान ने दावा किया है कि खुजस्तान प्रांत में अमेरिकी मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत हो गई,जबकि 8 घायल हुए हैं। अमेरिका ने प्रांत में 3 लोग की निशाना बनाया। रूस कथित तौर पर ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की तकनीक गुप्त रूप से दे रहा है।

छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 15 प्रकोष्ठों में तय किए चेहरे चुन्नीलाल साहू को बड़ी जिम्मेदारी, लामचंद बाफना भी बनाए गए सहसंयोजक

रायपुर,02 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रदेश के 15 प्रकोष्ठों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने अलग-अलग प्रकोष्ठों में संयोजक, सहसंयोजक और प्रभारी की जिम्मेदारियां तय की है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति के बाद नियुक्तियों की सूची जारी की गई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रभारी डॉ. नवीन मार्कण्डेय की ओर से नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया। नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने प्रकोष्ठों में संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा में प्रकोष्ठों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनके जरिए समाज के अलग-अलग वर्गों, व्यवसायों और क्षेत्रों से जुड़े लोगों तक पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाया जाता है। चुन्नीलाल साहू को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया : जारी सूची में पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लामचंद बाफना को प्रकोष्ठ संकुल सहसंयोजक बनाया गया है। दोनों नेताओं को अलग-अलग प्रकोष्ठों के बीच समन्वय और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। 15 प्रकोष्ठों में नई जिम्मेदारियां : भाजपा ने कुल 15 प्रकोष्ठों के लिए पदाधिकारियों की घोषणा की है। इनमें अलग-अलग सामाजिक और व्यावसायिक समूहों से जुड़े प्रकोष्ठ शामिल हैं। पार्टी का फोकस इन प्रकोष्ठों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों तक संगठन की पहुंच बढ़ाने पर है। भाजपा लगातार बुध से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दे रही है। ऐसे में प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियों को संगठन विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।



तमिलनाडु के 52 मंदिरों में स्मार्टफोन बैन: परिसर में सेल्फी और रील पर पाबंदी,वीआईपी पर भी लागू होंगे नियम

चेन्नई,02 सितंबर 2026। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन बैन लागू करने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह नियम मंगलवार से लागू हुआ है। नए नियम के मुताबिक, श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले स्मार्टफोन काउंटर पर जमा करना होगा। इसके लिए हर फोन पर 5 रुपये चार्ज देना होगा। बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। मंदिर परिसर में फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के तहत वीआईपी, बड़ी हस्तियां और मशहूर लोगों की फोटो या वीडियो बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स मंत्री रमेश ने यह जानकारी दी। यह फैसला 2 दिसंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट की मद्रु बैच के आदेश के आधार पर जारी किए गए हैं। मंदिर



परिसरों में श्रद्धालुओं,खासकर युवाओं द्वारा फोटो खींचने,रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही थीं। मंत्री ने कहा कि जिन मोबाइल फोन में कैमरा नहीं है, उन्हें मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। नए नियम का उद्देश्य मंदिरों की पवित्रता और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिख रहा छत्तीसगढ़ : उपराष्ट्रपति

रायपुर,02 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, भय और अभाव के साये से निकलकर आज शांति, प्रगति और अवसरों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जो क्षेत्र कभी हिंसा के लिए जाने जाते थे, वहां आज सड़कें,स्कूल,अस्पताल,कनेक्टिविटी और निवेश पहुंच रहे हैं। यह बात उपराष्ट्रपति सी. पी. रामाकृष्णन ने बुधवार को यहां अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने एम्स रायपुर को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के ऐतिहासिक परिवर्तन का एक प्रमुख प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि,उन्नत स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा अनुसंधान और ट्रांसप्लंटेशन के क्षेत्र में संस्थान की



उपलब्धियां सराहनीय हैं, जिनमें राज्य का पहला 'स्वैप किडनी ट्रांसप्लंट' भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हृदय प्रत्यारोपण कार्यक्रम की मंजूरी एक और महत्वपूर्ण

सफलता है। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों के मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान कर

सम्मानित किया। मध्य भारत के इस प्रतिष्ठित संस्थान में आयोजित समारोह में स्नातक (यूजी),स्नातकोत्तर (पीजी), सुपर-स्पेशियलिटी,डॉक्टरेट और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों के कुल 689 विद्यार्थियों (376 छात्राएं और 313 छात्र) को डिग्रियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह के मुख्य आकर्षणों में 'से नो टू ड्रुम्स' (नशे को ना कहें) की शपथ भी शामिल रही, जिसके तहत उपस्थित सभी विद्यार्थियों को स्वयं नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने और अपने साथियों व समाज में इसके दुष्प्रभावों व खतरों के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि,यह दीक्षांत समारोह

केवल उत्सव का क्षण नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का भी अवसर है। उन्होंने कहा,'आज आपको आपकी डिग्रियां मिल रही हैं और कल आपको इससे कहीं अधिक मूल्यवान जिम्मेदारी सौंपी जाएगी-भारत को जनता का स्वास्थ्य, विश्वास और जीवन।' इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका,केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुग्रिया पटेल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। वहीं, एम्स रायपुर की ओर से अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संजीव हांडा तथा कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल भी मंच पर मौजूद रहे।

बारिश में तालाब बनी कुंडला सिटी रहवासी बोले-हर साल यही हाल



संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने राजस्व कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण का दिया निर्देश

नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण समय-सीमा में हों निश्चित

—संवाददाता—
बलरामपुर, 02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने आज जिला बलरामपुर के प्रवास के दौरान तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय का निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखते हुए जनमानस से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर तत्परतापूर्वक निराकृत करने पर जोर दिया।

तहसील कार्यालय स्थित सेवा सेतु केंद्र का अवलोकन कर संभागायुक्त ने प्राप्त आवेदनों की स्थिति जानी और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मांश जमादार, नाजरात, कानूनगो शाखा, रिकॉर्ड रूम तथा

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालयों के प्रकरणों की जांच की। इस दौरान नकल शाखा में पंजी संधारण व्यवस्थित न मिलने तथा अद्यतन जानकारी के अभाव पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

न्यायालयीन प्रकरणों का अवलोकन करते हुए उन्होंने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा कब्जा से संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण और सभी अपंजीकृत प्रकरणों को अनिवार्य रूप से ई-कोर्ट प्रणाली में दर्ज करने के निर्देश दिए। रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों की समुचित लिस्टिंग तथा जमा व इश्यू पंजी दुरुस्त रखने को कहा, वहीं आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की जांच कर समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम कार्यालय के निरीक्षण में उन्होंने पांच वर्ष से अधिक अवधि के पुराने लंबित राजस्व प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर इनका प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा।

आस्था निकुंज में मूकबधिर बच्चों के साथ सेवा किटी सदस्यों ने मनाया सेवा दिवस



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 02 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सेवा किटी समूह की सदस्यों ने बुधवार को आस्था निकुंज मूकबधिर विद्यालय में बच्चों के साथ समय बिताया। इस विद्यालय में पहली से 12वीं तक 160 मूकबधिर बच्चे अध्ययनरत हैं। समूह की सदस्यों ने बच्चों को कांपी, पेन, पेंसिल, टॉफी, ब्रिस्कट और बैठने के लिए टाटपट्टी का वितरण किया। इसके साथ ही बड़ी छत्राओं को सेनेटरी पैड भी दिए गए। इस दौरान बड़ी बच्चियों को वर्तमान समय में समाज में हो रही समस्याओं से खुद को सुरक्षित रखने को लेकर जागरूक भी किया गया। किस तरह से अनजान लोगों से दूरी बनानी है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, इस पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संस्था की प्रिंसिपल श्वेता सिस्टर के साथ सेवा किटी की संस्थापिका वंदना दाता, मधु चौदह, सरिता भाटिया, लिली बसु राय, रश्मि गुप्ता, अतिशी भट्टाचार्य, स्मिता तिवारी एवं विद्यालय के सभी स्टाफ उपस्थित थे। सेवा किटी समूह ने निर्णय लिया है कि वे हर महीने एक बार परवाज कार्यक्रम के तहत आस्था निकुंज के बच्चों के बीच अपना समय देंगे और उनकी मदद करेंगे। साथ ही समूह के सदस्यों ने केशवपुर आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर वहां कार्य करने का भी निर्णय लिया है।

युवक ने कीटनाशक पीकर की आत्महत्या, प्रेम-प्रसंग में विवाद की आशंका

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 02 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के ग्राम अखोरा खुर्द में एक युवक ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। युवक का इलाज अम्बिकापुर में चल रहा था, यहां 2 सितंबर को उसकी मौत हो गई। पिता की रिपोर्ट पर राजपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अखोरा खुर्द का सोहन राम पिता बिर्बल राय 17 वर्ष, 9 अगस्त को सोहन ने अपना मोबाइल पटक कर तोड़ दिया था। पृष्ठने पर वह कुछ नहीं बताया, जबकि घर में किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ था। 18 अगस्त को शाम करीब 7 बजे पिता घर के बाहर थे, घर में मां और छोटा पुत्र सोहन था। दो अन्य लड़के दुकान तरफ गए थे। अचानक घर के अंदर से सोहन की मां शोर मचाई तो घर के बाहर मौजूद पिता और पड़ोसी पहुंचे, इस दौरान सोहन आंगन में उल्टी कर रहा था और कीटनाशक दवा का महक आ रहा था। परिजन जब कमरे में गए तो उसके बिस्तर के पास जमीन में कीटनाशक जहर का डिब्बा पड़ा था, ढक्कन खुला था और कुछ बूँदें जमीन पर गिरी थीं। स्वजन उसे जिला अस्पताल अम्बिकापुर लेकर गए, यहां करीब एक घंटे प्राथमिक इलाज चला। इसके बाद स्वजन किसी की सहमति से उसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर अस्पताल अम्बिकापुर में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 2 सितंबर को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता का कहना है कि, सोहन किसी लड़की से बातचीत करता था और दोनों के बीच मनमुटाव होने से नाराज होकर उसने संभवतः यह कदम उठाया होगा। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस मृतक के मोबाइल और अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी।

तालाब में नहाते वक्त काटा सांप, महिला की मौत

—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 02 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दशकर्म में गई महिला को तालाब में नहाते वक्त सांप काट लिया। स्वजन बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक, गांधीनगर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर खुर्द की जोसफीना टोप्पो पति स्व. निगम टोप्पो 35 वर्ष, मंगलवार को रिश्तेदारी में दशकर्म कार्यक्रम के दौरान अन्य महिलाओं के साथ गांव के ही तालाब में नहाने के लिए गई थी। नहाने के बाद ठीक नहीं लगने पर वह घर आ गई और अपने देवर नीलम कुमार को बताई के तालाब में नहाते वक्त सांप काट लिया है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गई। इस बीच घर में मौजूद पुत्र अपनी मां को आवाज लगाते हुए हिला-डुलाकर देखा तो वह नहीं उठी। मां के बेहोश होने की जानकारी वह अपने चाचा नीलम कुमार को दिया। स्वजन उसे आननफ्रानन में निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

पट्टा खत्म, फिर भी बॉक्सआइट खनन का आरोप; किसानों का फूटा गुस्सा...

लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी खनन और परिवहन का आरोप, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

—संवाददाता—
मैनपाट, 02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के ग्राम बरिमा में बॉक्सआइट खनन को लेकर किसानों का आक्रोश सामने आया है। प्रभावित भू-स्वामियों ने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएमडीसी) पर लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी उनकी जमीन से कथित रूप से खनन और बॉक्सआइट परिवहन कराने का आरोप लगाया है। किसानों ने जिला प्रशासन को जापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14 में 4 जनवरी 2017 को बरिमा की निजी भूमि सीएमडीसी को 7 वर्षों के लिए बॉक्सआइट उखनन के लिए दी गई थी। अनुबंध के अनुसार जनवरी 2024 में लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि लीज खत्म होने के बाद न तो जमीन मूल स्वरूप में लौटाई गई और न ही फसल व जमीन का पूरा मुआवजा दिया गया। इसके बावजूद पिछले दो वर्षों से संबंधित जमीन से बॉक्सआइट निकाले जाने का आरोप है।

350 टुक बॉक्सआइट निकालने का दावा : प्रभावित किसानों ने दावा किया है कि पिछले दो वर्षों में संबंधित खसरा नंबरों से करीब 350 टुक बॉक्सआइट निकालकर बाजार में बेचा गया। किसानों ने अवैध रूप से निकाले गए



स्थायी रूप से जमीन लौटाने की मांग

भू-स्वामियों ने प्रशासन से लीज और खनन अनुमति की वैधता की जांच, संबंधित खसरा नंबरों का भौतिक सत्यापन, पिछले दो वर्षों में निकाले गए बॉक्सआइट की मात्रा और उसके परिवहन-विक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमीन को मूल स्वरूप में वापस कराने की मांग की गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम बरिमा स्थित सीएमडीसी के कोर्टघर के पास बॉक्सआइट परिवहन रोककर आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग किसानों के आरोपों की जांच कर क्या कार्रवाई करते हैं।

बॉक्सआइट की कीमत का भुगतान कराने और भविष्य में उनकी जमीन पर कथित अवैध उखनन तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे केवल फसल मुआवजे के आधार पर अपनी जमीन खनन के लिए देने को तैयार नहीं हैं।

जनसुनवाई के वादों पर भी सवाल:

किसानों का कहना है कि बॉक्सआइट परियोजना की जनसुनवाई के दौरान सीएमडीसी की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार, विकास और उचित मुआवजे सहित कई आश्वासन दिए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन पर इन वादों का अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे भू-स्वामियों में नाराजगी बढ़ रही है।

अकेली देख महिला से जबरन दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बतौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

महिला संबंधी अपराधों पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए थाना बतौली पुलिस टीम ने दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को धरदबोचा और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

घर पर अकेली देखकर जबरन की थी दरिंदगी : थाना बतौली से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 1 सितंबर 2026 को थाने आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कदनई सुराडरिया निवासी जयप्रकाश पैकरा ने उसे घर पर अकेली पाकर उसकी बेबसी का फायदा उठाया। पीड़िता द्वारा लगातार मना करने और विरोध करने के बावजूद आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

घंटों जाम में फंसी रहीं गाड़ियां, बारिश ने बढ़ाई परेशानी, भारत माता चौक से दरिमा चौक तक एनएच-43 पर लगा लंबा जाम, गड़्यों में बोल्टर डालने से सड़क और संकरी

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

नेशनल हाईवे-43 पर भारत माता चौक से दरिमा चौक तक बुधवार को घंटों जाम की स्थिति बनी रही। बारिश के कारण सड़क पर पानी भरने और जगह-जगह गड़ों होने से वाहनों की रफ्तार थम गई। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगने से लोगों को भी परेशानी का



सामना करना पड़ा। भारी वाहनों के साथ चारपहिया वाहन भी सड़क पर रेंगते नजर आए। भाजपा

संगठन महामंत्री की फटकार के बाद सड़क के गड़्यों में बोल्टर डालकर भराव किया गया है। इससे छोटे वाहनों के लिए सड़क और खतरनाक हो गई है। बारिश का पानी भरने से गड़्यों का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। लोगों का कहना है कि हाईवे का निर्माण जल्द होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में रोजाना आवागमन मुश्किल हो रहा है।

44 लाख की राशि स्वीकृत, फिर भी राहत नहीं : भारत माता चौक से दरिमा चौक तक सड़क के नवनिर्माण के लिए करीब 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं कांग्रेस ने सड़क की बदहाली को लेकर प्रदर्शन कर जल्द निर्माण की मांग की है। इसके बावजूद फिन्हल लोगों को खराब सड़क और जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया।

पूछताछ में कबूला जुर्म, भेजा गया जेल

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर आरोपी जयप्रकाश पैकरा (24 वर्ष), आत्मज सुदामा पैकरा, निवासी कदनई सुराडरिया को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अपराध का पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम: इस पूरी त्वरित और सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार धुव, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलवो, राकेश एक्का और जोगी बड़ा की सराहीय व सक्रिय भूमिका रही।

सोनवर्षा के मासूमों का ‘बरसाती इम्तिहान’ नाला पार कर स्कूल जाने की मजबूरी

बारिश में बढ़ता पानी,घटती सुरक्षा: हादसे का इंतजार या पहले होगी व्यवस्था?

राजन पाण्डेय

मनैद्रागढ़,02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

मानसून आते ही ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में विकास के दावों की असली तस्वीर सामने आने लगती है, मनैद्रागढ़ क्षेत्र के सोनवर्षा वार्ड क्रमांक 07 से सामने आई तस्वीरें इसी जमीनी हकीकत को बयां कर रही हैं,यहां स्कूली बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए किसी सामान्य रास्ते से नहीं,बल्कि बरसात में उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है,बच्चों के कंधे पर स्कूल बैग है, हाथों में किताबें हैं और सामने तेज बहाव वाला पानी—ऐसे में हर कदम सिर्फ स्कूल की ओर नहीं,बल्कि जोखिम की ओर भी बढ़ता दिखाई देता है,सरकार की योजनाओं में बच्चों की शिक्षा,सुरक्षित आवागमन और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही जाती है,लेकिन सोनवर्षा की स्थिति इन दावों के सामने एक सीधा सवाल खड़ा करती है—क्या स्कूल तक पहुंचने के लिए किसी बच्चे को अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए?

**किताबों के साथ
नाला पार करते मासूम**

सोनवर्षा वार्ड क्रमांक 07 में बारिश के दिनों में नाले का जलस्तर बढ़ जाता है, स्थानीय स्तर पर सामने आई तस्वीरें और ग्रामीणों के अनुसार बच्चों को इसी पानी को पार कर स्कूल जाना पड़ता है, पानी का बहाव बढ़ने पर यह रास्ता और अधिक खतरनाक हो जाता है,जिस उम्र में बच्चों को स्कूल की कक्षा में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए,उसी उम्र में उन्हें पानी की गहराई, बहाव और फिसलन का अंदाजा लगाकर कदम बढ़ाना पड़ रहा है, एक तरफ स्कूल पहुंचने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ रास्ते में किसी अनहोनी की आशंका, सबसे चिंताजनक स्थिति तब बनती है, जब तेज बारिश के बाद नाले में अचानक पानी बढ़ जाता है, बरसाती नालों का जलस्तर स्थिर नहीं रहता, कुछ समय पहले तक सामान्य दिखने वाला रास्ता अचानक तेज बहाव वाली धारा में बदल सकता है। ऐसे में

स्कूल जाना शिक्षा का अधिकार,जोखिम उठाना मजबूरी क्यों?

शिक्षा बच्चों के भविष्य की बुनियाद है,लेकिन यदि विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता ही सुरक्षित नहीं है तो ग्रामीण बच्चों के सामने एक अजीब परिस्थिति पैदा हो जाती है,अभिभावकों के सामने भी दोहरी चिंता है,बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो पढ़ाई प्रभावित होगी और भेजेंगे तो रास्ते में उनकी सुरक्षा को लेकर डर बना रहेगा,खासकर छोटे बच्चों के मामले में यह चिंता और गंभीर हो जाती है,सवाल यह भी है कि यदि किसी बच्चे का पैर फिसल जाए,वह पानी के बहाव में गिर जाए या अचानक जलस्तर बढ़ जाए तो उस स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी?

बरसात में नाला बन जाता है ‘अधोषिखत परीक्षा केंद्र’

सोनवर्षा की तस्वीर को अगर व्यंग्यात्मक अंदाज में देखा जाए तो यहां बच्चों की पढ़ाई के साथ एक अतिरिक्त विषय भी जुड़ गया है नाला पार करने की कला,स्कूल बैग में किताबें हैं,लेकिन रास्ते में बच्चों को किताबों से ज्यादा पानी की गहराई और बहाव पर ध्यान देना पड़ता है, शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना होना चाहिए,मगर यहां रास्ता ही बच्चों की परीक्षा लेता नजर आ रहा है, यह स्थिति केवल एक सड़क या पुलिया की कमी नहीं बताती,बल्कि यह भी दिखाती है कि विकास की योजनाएं बनाते समय छोटी लेकिन बेहद जरूरी आधारभूत जरूरतों को कितना महत्व दिया जाता है।

छोटे बच्चों के लिए नाला पार करना बेहद जोखिमपूर्ण हो सकता है।

अभिभावकों के सामने मजबूरी, बच्चों के सामने जोखिम- स्थानीय लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान नाले का पानी बढ़ने पर बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, बच्चे शिक्षा से वंचित न हों, इसलिए उन्हें भेजना पड़ता है, लेकिन रास्ते का जोखिम हर समय डर पैदा करता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे भी शहरों के बच्चों की तरह सुरक्षित रास्ते से स्कूल पहुंचने के हकदार हैं, किसी बच्चे का ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र में रहना उसके लिए अतिरिक्त जोखिम का कारण नहीं होना चाहिए, यदि किसी इलाके में वर्षों से आवागमन की समस्या है और बरसात में वह समस्या जानलेवा रूप ले लेती है, तो उसे केवल मौसमी परेशानी मानकर छोड़ देना प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है।

विकास के दावों और जमीनी तस्वीर में कितना अंतर?— ग्रामीण इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया और आवागमन की सुविधाओं को लेकर लगातार विकास कार्यों की बातें होती हैं, लेकिन सोनवर्षा वार्ड क्रमांक 07 की तस्वीर यह पूछने को मजबूर करती है कि विकास की

योजनाओं की प्राथमिकता तय करते समय ऐसे रास्तों का सर्वेक्षण कितना गंभीरता से किया जाता है, एक तरफ बड़े विकास कार्यों की चर्चा होती है, दूसरी तरफ किसी छोटे से नाले पर सुरक्षित पुलिया का अभाव बच्चों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहा है, सवाल यह नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि समस्या के काफ़ी कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कब तक होते रहेंगे।

‘हादसा होने के बाद’ वाली व्यवस्था से कब मिलेगी मुक्ति?— ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं इस समस्या का समाधान किसी दुर्घटना के बाद करने की परंपरा न बन जाए, अक्सर किसी घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, स्थिति का जायजा लिया जाता है और कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि जब खतरा पहले से दिखाई दे रहा है तो हादसे का इंतजार क्यों? सोनवर्षा में बच्चों का नाला पार करना कोई छिपी हुई समस्या नहीं है, तस्वीरें खुद इस स्थिति की गंभीरता बयान कर रही हैं, ऐसे में संबंधित विभागों को मौके का निरीक्षण कर यह पता लगाना चाहिए कि यहां स्थायी पुलिया, पुल या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की क्या आवश्यकता है।



सोनवर्षा के मासूमों का ‘जल-परीक्षा’ वाला स्कूल सफर
वार्ड क्रमांक 07 में नाला बना बच्चों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा

जिम्मेदारी तय करने की जरूरत

यदि किसी बच्चे के साथ नाला पार करते समय दुर्घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेगा कि संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को इस जोखिम की जानकारी थी या नहीं, क्या पंचायत ने इस समस्या को चिन्हित किया है? क्या संबंधित विभाग ने स्थल का निरीक्षण किया है? क्या पुलिया निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है? क्या स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को अवगत कराया है? इन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है।

पहले अस्थायी व्यवस्था,फिर स्थायी समाधान

स्थायी पुलिया या सुरक्षित मार्ग बनने में यदि समय लगता है तो तब तक प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए,बारिश के दिनों में बच्चों को जोखिम वाले रास्ते से रोकने,सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में निगरानी व्यवस्था करने जैसे कदम तत्काल उठाए जा सकते हैं,इसके साथ ही नाले की तकनीकी स्थिति, जल प्रवाह और बरसात में अधिकतम जलस्तर का आकलन कर स्थायी निर्माण की योजना तैयार करना जरूरी होगा।

सोनवर्षा पूछ रहा है...किताबें मारी हैं या व्यवस्था की चुप्पी?

सोनवर्षा वार्ड क्रमांक 07 की तस्वीर सिर्फ बच्चों के नाला पार करने की तस्वीर नहीं है, यह ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं पर सवाल है, यह उस व्यवस्था से सवाल है,जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए किताबों के साथ जोखिम भी लेकर निकलते हैं, बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए,पानी के तेज बहाव में संतुलन बनाने की मजबूरी नहीं,उनके रास्ते में स्कूल की घंटी होनी चाहिए, खतरों की धारा नहीं,अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन इस समस्या को केवल बरसात की मौसमी परेशानी न मानकर बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ा गंभीर विषय समझे, संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण करें, तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और स्थायी पुलिया अथवा सुरक्षित मार्ग के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाएं, क्योंकि किसी मासूम के बह जाने के बाद पुलिया बनाना विकास नहीं, बल्कि व्यवस्था की देर से जागी संवेदना होगी, सोनवर्षा के बच्चों को हादसे का इंतजार नहीं, सुरक्षित रास्ता चाहिए।

सर्वसम्मति से अमृतांशु मिश्रा बने तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कोरिया जिला अध्यक्ष

—संवाददाता—
कोरिया 02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।



छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला कोरिया इकाई की बैठक में संगठनात्मक बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, बैठक में अमृतांशु मिश्रा को सर्वसम्मति से संगठन का कोरिया जिला अध्यक्ष घोषित किया गया, उनके नाम की घोषणा होते ही उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारी साथियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। बैठक के दौरान अमृतांशु मिश्रा ने संगठन की आजीवन सदस्यता भी ग्रहण की, इस अवसर पर कर्मचारी साथियों ने उनका स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में जिले में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को मजबूती के साथ संबोधित मंचों पर उठाना जाएगा।

कर्मचारी हितों के मुद्दों को प्राथमिकता देने की उम्मीद- नवनिवृत्त जिला अध्यक्ष अमृतांशु मिश्रा को संगठन के पदाधिकारियों ने सक्रिय,ऊर्जावान एवं कर्मचारियों के बीच सहज संवाद रखने वाला साथी बताते हुए उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। पदाधिकारियों का

कहना है कि कर्मचारी हितों से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे में नए नेतृत्व के सामने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के साथ कर्मचारियों की समस्याओं को एकजुट होकर उठाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी,बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, सदस्यता विस्तार तथा कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और जिले के अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया।

संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प- जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद अमृतांशु मिश्रा ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाने की बात

कही,उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया,उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती सामूहिक प्रयासों से ही संभव है,कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए सभी साथियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा,उन्होंने कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों में संगठन की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

पदाधिकारियों ने जताया विश्वास-बैठक में उपस्थित प्रदेश एवं संभागीय पदाधिकारियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अमृतांशु मिश्रा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं, पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कोरिया जिला इकाई में संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी और कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों को प्रभावी तरीके से सामने रखा जा सकेगा, बैठक के अंत में उपस्थित कर्मचारी प्रतिनिधियों ने संगठन की एकजुटता बनाए रखने तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का संकल्प लिया।

17 वर्ष पूर्व के मामले में जारी स्थाई वारंट तामिल,आरोपी गिरफ्तार..

- थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा स्थाई वारंट किया गया तामिल।
- एक्सीडेंट के मामले में जारी वारंट पर की गई कार्यवाही।
- आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश।

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.सं.) द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में लंबित स्थाई वारंट/गिरफ्तारी वारंट की तामिली कर वर्षों से फरार चल रहे वारंटियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आ.क्रमांक 265/09 धारा 279, 337, 338 भा.द.वि. के मामलों में फरार चल रहे आरोपी रामभरत विश्वकर्मा आत्मज ननका विवश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष साकिन शिव मंदिर के पास थाना गांधीनगर के प्रकरण में उपस्थित नहीं रहने पर



माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थाई वारंट जारी किया गया था, आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु जारी स्थाई वारंट के अनुसार थाना कोतवाली पुलिस टीम के प्रयास से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को पकड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

40 साल की सेवा के बाद निरीक्षक जे.एस.कंवर और एसआई रामप्रताप साहू सेवानिवृत्त

पुलिस विभाग ने भावभीनी विदाई देकर किया सम्मान,एसपी योगेश कुमार पटेल ने शॉल-श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट किए



—संवाददाता—
सूरजपुर,02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

पुलिस विभाग में वर्षों तक अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ सेवाएं देने के बाद निरीक्षक जे.एस. कंवर एवं उप निरीक्षक रामप्रताप साहू सोमवार,31 अगस्त 2026 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, जिला पुलिस कार्यालय सूरजपुर में आयोजित विदाई समारोह में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को भावभीनी विदाई दी और उनके लंबे सेवाकाल को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की।

निरीक्षक जे.एस. कंवर ने पुलिस विभाग में 40 वर्ष 5 माह तथा उप निरीक्षक रामप्रताप साहू ने 35 वर्ष 10 माह तक अपनी सेवाएं दीं। दोनों अधिकारियों के लिए यह सेवानिवृत्ति केवल शासकीय सेवा से विदाई का अवसर नहीं,बल्कि दशकों लंबे पुलिस सेवाकाल के अनुभवों,जिम्मेदारियों और यादों को समेटने का भी भावुक क्षण रहा।

एसपी ने किया सम्मानित-विदाई समारोह में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भा.पु.सं) ने दोनों अधिकारियों

को उनके दीर्घ सेवाकाल एवं विभाग के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया, पुलिस अधीक्षक ने शॉल,श्रीफल,स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट कर दोनों अधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया,इस अवसर पर एसपी योगेश कुमार पटेल ने कहा कि पुलिस विभाग में चार दशक से अधिक समय तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सेवाएं देना अपने आप में गौरवपूर्ण उपलब्धि है,उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों ने अपने सेवाकाल में जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया तथा अपने अनुभवों से अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन भी किया।

उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़ी होती है,कानून-व्यवस्था का सुर्क्षा तथा जरूरत के समय लोगों की सहायता करने में पुलिसकर्मीयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दोनों अधिकारियों ने लंबे सेवाकाल के दौरान इन दायित्वों का निर्वहन किया, एसपी ने उनके स्वस्थ,सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।



अनुभव साझा करते हुए हुए भावुक- समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे निरीक्षक जे.एस. कंवर एवं उप निरीक्षक रामप्रताप साहू ने भी पुलिस सेवा के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया, उन्होंने अपने सेवाकाल में सामने आई चुनौतियों,महत्वपूर्ण कार्यवाहियों और यादगार घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस सेवा में रहते हुए आमजन की सुरक्षा और सेवा को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया, दोनों अधिकारियों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों,सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि लंबे समय तक एक परिवार की तरह पुलिस विभाग के साथ काम करने के बाद सेवा से विदाई लेना भावुक क्षण है। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद भी पुलिस विभाग और सहकर्मियों से जुड़ी यादें हमेशा साथ रहेंगी।

परिजनों की मौजूदगी ने बढ़ाया भावुक पल-विदाई समारोह में जिला पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बिताए सेवाकाल के अनुभवों को याद किया, सहकर्मियों ने उनके व्यवहार, कार्यशैली और

विभागीय योगदान की चर्चा करते हुए उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं, समारोह में सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिजनों की मौजूदगी ने माहौल को और भावुक बना दिया। पुलिस परिवार के सदस्यों ने भी दोनों अधिकारियों के स्वस्थ एवं सुखमय भविष्य की कामना की।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवागन,एसडीओपी सूरजपुर अधीक्षक पैरार,सीएसपी बेनाई कुजूर,डीएसपी मुख्यालय महलक्ष्मी कुलदीप एवं रक्षित निरीक्षक अशोक गिरी सहित जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिजन उपस्थित रहे, समारोह में अधिकारियों के कर्मचारियों ने दोनों सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के दीर्घ सेवाकाल को सम्मान के साथ याद करते हुए कहा कि उनकी सेवाएं विभाग के लिए महत्वपूर्ण रही हैं,पुलिस विभाग की ओर से उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की गई।

पीएचडी प्रवेश परीक्षा 18 सितंबर को, प्रवेश पत्र वितरण शुरू

—संवाददाता—
अम्बिकापुर,02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

संत गाँध्या गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा की पीएचडी प्रवेश परीक्षा-2026 के लिए प्रवेश पत्र वितरण शुरू हो गया है। परीक्षा 18 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सरस्वती महाविद्यालय, सुभाषनगर अम्बिकापुर में होगी। विश्वविद्यालय ने विषयवार अर्धार्थियों की सूची भी वेबसाइट पर जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की 24 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार अर्धार्थी 1 से 16 सितंबर तक कार्यालयीन समय में प्रशासनिक भवन स्थित छत्र सहायता केंद्र से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र मिलने के बाद अर्धार्थियों को नाम, विषय, फोटो सहित अन्य विवरणों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। नुति होने पर अकादमिक विभाग से संपर्क कर तत्काल सुधार कराना होगा।

खराब सड़क को लेकर कांग्रेस का चक्काजाम,मिला लिखित आश्वासन सीतापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में प्रदर्शन,15 अक्टूबर के बाद नवनिर्माण का भरोसा

—संवाददाता—
सीतापुर,02 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सड़क की बदहाली और मरम्मत की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में सीतापुर में चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री के निवास के सामने दोपहर 12 बजे आयोजित जनसभा में उन्होंने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक पर सड़क की अनदेखी का आरोप लगाया। अमरजीत भगत ने कहा कि तीन साल में विधायक सीतापुर की करीब तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं करा सके।



सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

प्रशासन और संबंधित विभाग को कई बार चेतावनी देने के बावजूद

समस्या का समाधान नहीं किया गया। जनसभा के बाद दोपहर

करीब 3 बजे कांग्रेसियों ने नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

15 अक्टूबर के बाद शुरू होगा नवनिर्माण : प्रदर्शन के दौरान एसडीएम और नेशनल हाईवे के इंजीनियर की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया। पूर्व मंत्री ने बताया कि 15 अक्टूबर के बाद सड़क का नवनिर्माण शुरू किया जाएगा। इससे पहले सड़क के सभी गड्ढों को भरने का आश्वासन दिया गया है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेसियों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया।

बैकुंठपुर की सड़क चौड़ीकरण मांग को मिली 88.51 करोड़ की मंजूरी क्या चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्ष का बड़ा मुद्दा अपने पाले में कर लिया?



खरवत चौक से जमगहना तक 13 किमी मार्ग होगा 4-लेन

● विधायक **भैयालाल राजवाड़े** के प्रयासों को भाजपा ने दिया श्रेय

● घड़ी चौक पर **आतिशबाजी** कर मनाया जश्न, मिष्ठान वितरण

● मुख्यमंत्री **विष्णुदेव साय**, वित्त मंत्री **ओपी चौधरी** के प्रति आभार

चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव: बैकुंठपुर की सड़क चौड़ीकरण मांग पर 88.51 करोड़ की मुहर

बैकुंठपुर की सड़क चौड़ीकरण मांग को मिली 88.51 करोड़ की मंजूरी क्या चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्ष का बड़ा मुद्दा अपने पाले में कर लिया ?

खरवत चौक से जमगहना तक 13 किमी सड़क होगी 4-लेन, विधायक भैयालाल राजवाड़े के प्रयासों का भाजपा ने दिया श्रेय, घड़ी चौक में आतिशबाजी कर मनाया जश्न

जिस सड़क पर घिर सकती थी भाजपा, उसी पर अब श्रेय की सियासत, बैकुंठपुर 4-लेन को 88.51 करोड़ मंजूर

बैकुंठपुर में सड़क चौड़ीकरण की राह साफ, भाजपा के हाथ लगा चुनावी 'विकास कार्ड'

सड़क चौड़ीकरण पर सरकार की मुहर, विधायक भैयालाल राजवाड़े के प्रयासों को भाजपा ने बताया बड़ी उपलब्धि

वर्षों की मांग पूरी, चुनावी मुद्दा हुआ कमजोर? बैकुंठपुर 4-लेन के लिए 88.51 करोड़ स्वीकृत

बैकुंठपुर की सड़कों पर विकास की '4-लेन' पटकथा, चुनाव से पहले भाजपा ने साधा बड़ा निशाना

घड़ी चौक पर आतिशबाजी, सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति पर भाजपा का जश्न... अब काम शुरू होने का इंतजार

-रवि सिंह-

कोरिया, 02 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर शहर की लंबे समय से चली आ रही सड़क चौड़ीकरण की बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार शासन की स्वीकृति तक पहुंच गई है, छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने खरवत चौक से गेज नदी पुल होते हुए जमगहना मुख्य मार्ग तक करीब

13 किलोमीटर सड़क का होगा 4-लेन विकास

लोक निर्माण विभाग के आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल इस परियोजना के तहत जिला कोरिया में खरवत चौक (एनएच-43) से गेज नदी पुल होते हुए जमगहना मुख्य मार्ग (एनएच-43) तक 13 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव है, इस मार्ग को 4-लेन के रूप में विकसित किया जाना है, परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 8851.29 लाख रुपये निर्धारित की गई है, यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शासन के दस्तावेज में इसे प्रशासकीय स्वीकृति कहा गया है, इसलिए इसे सीधे तौर पर निर्माण पूरा होने या पूरी राशि तत्काल जारी हो जाने के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी स्वीकृति, डिजाइन अनुमोदन, निविदा और भूमि से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

13 किलोमीटर सड़क को 4-लेन में विकसित करने के लिए 8851.29 लाख रुपये यानी 88 करोड़ 51 लाख 29 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, शासन का यह आदेश 1 सितंबर 2026 को जारी हुआ है।

लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण को लेकर शहर के युवाओं, व्यापारियों और नागरिकों के बीच मांग उठती रही है, ऐसे में इस स्वीकृति को केवल एक सड़क परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि बैकुंठपुर की स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, खासकर नगरीय राजनीति में यह सवाल उठने लगा है कि जिस सड़क चौड़ीकरण को लेकर आने वाले चुनाव में भाजपा से सवाल किए जा सकते थे, क्या शासन की स्वीकृति के बाद वही मुद्दा अब भाजपा के लिए उपलब्धि का मुद्दा बन गया है? हालांकि, यह राजनीतिक आकलन है और इसका अंतिम असर चुनाव में जनता के रुख से ही तय होगा, फिलहाल इतना जरूर है कि सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक बहस में अब सत्ता पक्ष के पास दिखाने के लिए शासन की स्वीकृति का दस्तावेज मौजूद है।

विधायक भैयालाल राजवाड़े के प्रयासों को दिया जा रहा श्रेय

सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति के बाद

भाजपा संगठन ने इसका श्रेय स्थानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े के प्रयासों को दिया है, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी की ओर से जारी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, प्रभारी मंत्री और विधायक के प्रति आभार जताया गया है, भाजपा का कहना है कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद विधायक ने सड़क चौड़ीकरण को प्राथमिकता में रखते हुए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए, मुख्यमंत्री और वित्त विभाग तक इस मांग को पहुंचाने तथा परियोजना को स्वीकृति दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए गए, वहीं भाजपा ने इसे वर्षों पहले शहर के युवाओं द्वारा उठाई गई मांग से भी जोड़ते हुए कहा है कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान युवाओं ने सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आवाज उठाई थी, संगठन के अनुसार उस समय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था, इस लिहाज से भाजपा अब इसे सरकार, विधायक, संगठन और शहरवासियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बता रही है।

क्या चुनावी वर्ष में बड़ा मुद्दा बनने से पहले ही भाजपा ने खत्म कर दिया सवाल?

सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर बैकुंठपुर की राजनीति में लंबे समय से चर्चा होती रही है, शहर का बढ़ता यातायात, संकरी सड़कें और भविष्य में शहर के विस्तार की जरूरत को देखते

स्वीकृति के बाद भाजपा ने घड़ी चौक पर मनाया जश्न

शासन की स्वीकृति की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, बैकुंठपुर के घड़ी चौक में आतिशबाजी कर और मिष्ठान वितरण कर सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति का जश्न मनाया गया, इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े तथा भाजपा जिला अध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया, भाजपा की ओर से इस स्वीकृति को बैकुंठपुर शहर के विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, पार्टी का कहना है कि शहर की वर्षों पुरानी मांग को शासन तक पहुंचाने और उसके लिए लगातार प्रयास करने में स्थानीय विधायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हुर यह मांग लगातार उठती रही, यही वजह है कि राजनीतिक दृष्टि से भी यह सवाल महत्वपूर्ण है कि यदि सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति नहीं मिलती तो क्या आगामी नगरीय चुनाव में यह भाजपा के खिलाफ एक बड़ा स्थानीय मुद्दा बन सकता था? विपक्ष के लिए यह कहना आसान होता कि शहर की वर्षों पुरानी मांग पूरी नहीं हुई, युवाओं और व्यापारियों की मांग का हवाला देकर सत्ता पक्ष से जवाब मांगा जा सकता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। शासन ने परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है और भाजपा के पास जनता के सामने रखने के लिए सरकारी आदेश मौजूद है, इसलिए राजनीतिक रूप से भाजपा को निश्चित तौर पर एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, जिसे वह 'मांग से स्वीकृति तक' की अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है, हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा पूरी तरह समाप्त हो गया, अब विपक्ष के पास स्वीकृति के बाद निविदा कब होगी, निर्माण कब शुरू होगा, काम कितने समय में पूरा होगा और गुणवत्ता कैसी रहेगी, जैसे सवाल उठाने का अवसर रहेगा।

अब असली परीक्षा स्वीकृति के बाद

सरकारी आदेश में परियोजना को लेकर कई महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं, आदेश के अनुसार तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद ही निविदा आमंत्रित की जाएगी, ड्राइंग और डिजाइन का

सक्षम अधिकारी से अनुमोदन भी आवश्यक होगा, इसके अलावा प्रस्तावित निर्माण के लिए कम से कम 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होने की शर्त रखी गई है, आदेश में यह भी कहा गया है कि निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो और निर्धारित नियमों का पालन किया जाए, स्वीकृत बजट की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, यदि कार्य के दौरान स्वीकृत राशि या प्रस्तावित कार्य में निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि होती है अथवा नया कार्य जोड़ा जाता है तो उसके लिए नियमानुसार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

अब सवाल यह नहीं कि सड़क चौड़ी होगी या नहीं, सवाल यह है कि कब होगी?

बैकुंठपुर की सड़क चौड़ीकरण परियोजना को 88.51 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद वर्षों पुरानी मांग ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर पार कर लिया है, भाजपा ने इसका स्वागत करते हुए इसे विधायक भैयालाल राजवाड़े के प्रयासों और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नगरीय चुनाव के पहले यह स्वीकृति भाजपा के लिए निश्चित रूप से एक

शहर के युवाओं और व्यापारियों की नजर अब निर्माण पर

स्वीकृति के बाद शहरवासियों में उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन वर्षों से इस सड़क का इंतजार कर रहे लोगों की निगाह अब अगले चरण पर है, लोगों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि निविदा प्रक्रिया कब पूरी होती है और जमीन पर काम कब शुरू होता है, सड़क चौड़ीकरण पूरा होने के बाद इससे बैकुंठपुर शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने, व्यापारिक गतिविधियों को गति देने और भविष्य की बढ़ती आबादी एवं वाहनों के दबाव को संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है, भाजपा इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं राजनीतिक तौर पर यह उपलब्धि स्थानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस मांग को लेकर उन्हें पहले आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उसी मांग की अब शासन स्तर पर स्वीकृति सामने आ चुकी है।

मजबूत स्थानीय उपलब्धि बन सकती है, जिस मुद्दे को विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, अब उसी मुद्दे पर भाजपा जनता के बीच जाकर यह दावा कर सकती है कि सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए 88 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दिलाई है, लेकिन कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी है, स्वीकृति के बाद निविदा, भूमि, तकनीकी प्रक्रिया और वास्तविक निर्माण—यही तय करेगा कि बैकुंठपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग कागज से निकलकर सड़क पर कब दिखाई देती है, और शायद आने वाले समय में राजनीतिक सवाल भी इसी के आसपास होगा— 'स्वीकृति किसने दिलाई?' से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होगा, 'काम कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ?'

किसानों के हित में बड़ी पहल, कोडांगी नहर के जीर्णोद्धार को मिली स्वीकृति

पोंडीडीह-कोडांगी क्षेत्र के किसानों का लंबा इंतजार खत्म... बारिश के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य

-संवाददाता-

खड़गवां, 02 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

क्षेत्र के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है, लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी पोंडीडीह-कोडांगी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कोडांगी नहर के जीर्णोद्धार कार्य को आखिरकार स्वीकृति मिल गई है, बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद नहर के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किए जाने की बात कही गई है।

जनपद सदस्य एवं सहकारिता एवं उद्योग समिति के सभापति युगांतर श्रीवास्तव ने बताया कि कोडांगी नहर की जर्जर स्थिति को लेकर लगातार किसानों की आवाज प्रशासन एवं संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाती रही, जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठकों में भी कई बार नहर की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाते हुए

इसके तत्काल मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की मांग रखी गई, उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर डॉ. राहुल वैकट को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया

कोडांगी क्षेत्र के किसानों को लंबे समय से नहर की खराब स्थिति के कारण सिंचाई संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, नहर के जीर्णोद्धार की स्वीकृति मिलने के बाद अब क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है, इससे कृषि कार्य को मजबूती मिलने के साथ ही किसानों को राहत मिलने की संभावना है, युगांतर श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों के लंबे इंतजार के बाद नहर के जीर्णोद्धार को स्वीकृति मिलना क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उन्होंने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने के लिए तत्कालीन कलेक्टर डॉ. राहुल वैकट के प्रति आभार भी व्यक्त किया, क्षेत्रवासियों और किसानों की निगाहें बारिश के बाद शुरू होने वाले निर्माण कार्य पर टिकी हैं, किसानों को उम्मीद है कि नहर का जीर्णोद्धार समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में सिंचाई के लिए उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

था, किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन कलेक्टर द्वारा संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने और कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए थे।

किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था होगी मजबूत

युगांतर श्रीवास्तव

जनपद सदस्य एवं सभापति, सहकारिता एवं उद्योग समिति



